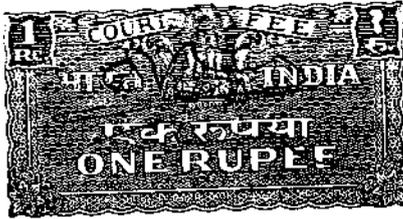
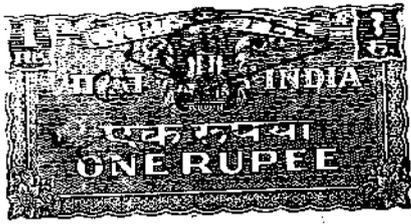


107



6-50 मूद्रा राजराजसिंह तनय नागेश्वर सिंह निवासी ग्राम-ज्मोड़ी तहसील-
 गोपद बनास, जिला-सीधी ४०९०० - - - - - आवेदक
 १२०-११९६

श्री शंकरजी पतनजी
 श्री गणेशजी शंकर
 १४.११.९६

केस
 १-
 २-

- १- श्रीपसरानु श्री मान सिंह निवासी ग्राम-ज्मोड़ी तहसील
 गोपद बनास जिला-सीधी ४०९०० केसदार
- २- बसन्त सिंह गोपद बनास जिला-सीधी ४०९०० केसदार
- ३- मुसो सरोज देवी पत्नी राजकरण सिंह गहरवार निवासी ग्राम पावा,
 तहसील-पुरहट, जिला-सीधी ४०९००
- ४- मुसो अरुण देवी पत्नी अवधाराज सिंह निवासी ग्राम-जद तहसील-
 सीधी ४०९००
- ५- मध्य प्रदेश सरकार - - - - - अनावेदक गण

१२१-११-९६
 २६-११-९६
 १२६-११-९६

२६-११-९६
 २६-११-९६

निगरानी विरुद्ध आवेदन श्री अमर आयुक्त
 रोवा सम्भाग रोवा प्रकरण क्रमांक-५७/
 अपील/११-९२ निर्णय दिनांक ११-१०-९६
 जिसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गोपद
 बनास जिला-सीधी द्वारा पारित आदेश
 दिनांक-३१-७-९२ को वैध माना गया है।

निगरानी अन्तर्गत धारा ५० ४०९०० भू-
 राजस्व सीधता १९५९.

मान्यवर,
 संक्षेप में प्रकरण के सूक्ष्म तथ्य इस तरह है, कि पक्षकारानों की
 समस्त पै त्रिक भूमियां ग्राम-ज्मोड़ी तहसील गोपद बनास जिला-सीधी में
 स्थित है, जिसका कोई भी प्रभावशाली बटवारा आज तक नहीं हुआ, पक्षका-
 रान मूल पुरुष रन्जोर सिंह को सन्ताने हैं। रन्जोर सिंह को मृत्यु के उपरांत
 उनके वार पुरो में से केवल एक ही पुरुष के मृतक गिरोमणि सिंह के नाम

M
 J

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी ¹²⁸~~2323~~-तीन/06 जिला -सीधी

स्थान दिनांक	तथा कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
29-6.16	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री एस० के० श्रीवास्तव उपस्थित होकर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 539/अपील/91-92 में पारित आदेश दिनांक 11.10.96 के विरुद्ध म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि अनावेदक केशव सिंह ने विचारण न्यायालय में इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम जमोड़ीकला में स्थित सर्वे क्रमांक 17 एवं 18 इसका नया नम्बर 18 एवं 19 है इसके भूमिस्वामी शिरोमणि सिंह थे उन्होंने जरिये रजिस्ट्री उनकी मां छविराजू के नाम 1964 में कर दी थी जिसका नामांतरण दिनांक 15.3.69 को उनकी मां के नाम हो गया था लेकिन पटवारी अभिलेखों में उक्त नामांतरण का अमल नहीं किया जिसके कारण उनके नाना शिरोमणि</p>	

//2// निग0 128-तीन/96

सिंह का नाम चला आया । चूंकि उनकी मां छविराजू का देहांत हो गया है इस कारण उनके द्वारा नामांतरण किये जाने हेतु निवेदन किया गया था। विचारण न्यायालय ने उनका आवेदन निरस्त कर दिया गया इससे परिवेदित होकर उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास जिला सीधी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपीलांट की अपील में पारित आदेश दिनांक 31.7.92 स्वीकार की गई है। इससे दुखी होकर आवेदक राजराखन सिंह ने अपर आयुक्त रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 11.10.96 को अनुविभागीय अधिकारी को आदेश स्थिर रखते हुये अपीलांट की अपील निरस्त कर दी गई। इसके विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3- आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास द्वारा यह नहीं देखा है कि अनावेदक क्या नामांतरण कार्यवाही में हित रखता है या नहीं उक्त न्यायालय ने अनावेदक कब्जे रखल के विवाद से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किया था तथा यह सिद्ध किया था कि विवादित भूमियों में स्थल पर उसी का कब्जा दखल है व हितधारी व्यक्ति है। उनके द्वारा अपने

//3// निग0 प्र0क0 128-तीन/96

तर्क में यह भी कहा गया है कि नामांतरण के पूर्ण इशतहार ही जारी नहीं किया गया है और न ही हितबद्ध पक्षकारों को सुना गया है । नामांतरण होने के पश्चात इशतहार जारी किया गया है । उनके द्वारा तर्क में कहा गया है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया नामांतरण अवैधानिक है । अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जावे ।

4- अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि आवेदक राजराखन सिंह का नामांतरित भूमियों में कोई स्वत्व नहीं है। कब्जे के आधार पर नामांतरण प्रमाणित नहीं किया जा सकता है।

5- उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने । उपलब्ध अभिलेखों का अध्ययन किया। विवादित भूमियों के भूमिस्वामी वर्ष 83-84 से 87-88 तथा 78-79 से 82-83 तथा वर्ष 75-76 से 77-78 तक के खसरो में विवादित भूमि के भूमिस्वामी शिरोमणि सिंह अंकित है ऐसा अपने आदेश में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उल्लेख किया है। शिरोमणि अपनी पुत्री छविराजू पत्नी श्री भानसिंह वघेल के पक्ष में दिनांक 20.11.64 को संपादित किया गया है । राजस्व निरीक्षक

M

//4// निग0 128-तीन/96

द्वारा दान पत्र के साथ नामांतरण भी किया जा चुका है। लेकिन पटवारी की त्रुटि के कारण कागजात में इसका इन्द्राज नहीं हुआ। पटवारी की गलती के कारण अनावेदक को इस प्रकार की कार्यवाही करनी पड़ी, जबकि अधीनस्थ न्यायालय का कर्तव्य था कि नामांतरण पंजी के अनुसार पटवारी रिकार्ड को अद्यतन करें।

“भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 109, 110-नामांतरण कार्यवाही में इशतहार का प्रकाशन सम्यकरूप से किया गया। ग्राम पंचायत को सूचना दी गई, ग्राम में डोढ़ी पिटवाकर मुनादी कराई गई। सभी प्रक्रियाओं का पालन कर नामांतरण आदेश जारी किया गया। राजस्व अधिकारी द्वारा प्रक्रियात्मक त्रुटि की गई, जिसका खामियाजा अनपढ़ ग्रामीणों को नहीं भुगताया जा सकता,,

6- उपरोक्त विवेचन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अपर आयुक्त रीवा एवं अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास के आदेशों से मैं सहमत हूँ और उनमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। अतः आवेदक की निगानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 11.10.96 स्थिर रखा जाता है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापस हों। राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।


सदस्य

M